

Daily करेंट अफेयर्स

➤ 28 & 29 सितम्बर 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मेक इन इंडिया पहल की 11वीं वर्षगांठ मनाई।



25 सितंबर 2025 को, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'मेक इन इंडिया' पहल की 11वीं वर्षगांठ मनाई और भारत की आर्थिक वृद्धि, विनिर्माण क्षमताओं और उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में इसकी भूमिका पर ज़ोर दिया। इस पहल ने भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित किया है।

- भारत को डिज़ाइन और विनिर्माण के वैश्विक केंद्र में बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2014 को 'मेक इन इंडिया' पहल शुरू की गई थी। इसके उद्देश्यों में निवेश को सुगम बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना, विश्व स्तरीय विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण, व्यापार सुगमता में सुधार और कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल है।

- इस पहल का नेतृत्व भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoC&I) के अंतर्गत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा किया जाता है। DPIIT प्रभावी नीति कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, उद्योग निकायों और निवेशकों के साथ समन्वय करता है।

- 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, MoC&I ने 20 सितंबर 2025 को 100 रुपये का स्मारक सिक्का लॉन्च किया, जो मेक इन इंडिया

के तहत विनिर्माण और औद्योगिक विकास में भारत की यात्रा का प्रतीक है।

Key Points:-

(i) पिछले 11 वर्षों में, मेक इन इंडिया ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा दिया है, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया है, तथा स्टार्टअप और उद्यमिता को प्रोत्साहित किया है।

(ii) इसने ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, रक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों को मजबूत किया है, जिससे भारत एक प्रतिस्पर्धी वैश्विक विनिर्माण खिलाड़ी के रूप में स्थापित हुआ है।

2. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये की 4-स्तंभ रणनीति को मंजूरी दी।



24 सितंबर 2025 को, प्रधान मंत्री (PM) नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के जहाज निर्माण और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए 69,725 करोड़ रुपये की 4-स्तंभ रणनीति को मंजूरी दी।

- इस योजना का उद्देश्य घरेलू क्षमता को बढ़ाना, दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करना, शिपयार्ड विस्तार का समर्थन करना, तकनीकी कौशल विकसित करना और नीतिगत सुधारों को लागू

करना है ताकि 2047 तक भारत को वैश्विक जहाज निर्माण में अग्रणी स्थान मिल सके।

- स्तंभ 1 के अंतर्गत, 19,989 करोड़ रुपये के बजट के साथ जहाज निर्माण विकास योजना (SbDS) को मंजूरी दी गई। इस योजना का उद्देश्य भारत की घरेलू जहाज निर्माण क्षमता को 4.5 मिलियन सकल टन भार (GT) प्रति वर्ष तक बढ़ाना है, जिससे वाणिज्यिक और रक्षा जहाजों के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा।

- स्तंभ 2 समुद्री क्षेत्र के वित्तपोषण पर केंद्रित है। जहाज निर्माण परियोजनाओं, आधुनिकीकरण और क्षेत्रीय विकास के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु 25,000 करोड़ रुपये की राशि के साथ समुद्री विकास कोष (MDF) को मंजूरी दी गई है।

Key Points:-

(i) स्तंभ 3 में जहाज निर्माण वित्तीय सहायता योजना (SBFAS) शामिल है, जिसे 31 मार्च 2036 तक बढ़ाया गया है और इसका कुल परिव्यय 24,736 करोड़ रुपये है, जिसमें 4,001 करोड़ रुपये का शिपब्रेकिंग क्रेडिट नोट आवंटन भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, सभी पहलों की देखरेख के लिए राष्ट्रीय जहाज निर्माण मिशन (NSM) की स्थापना की जाएगी, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को जहाज निर्माण में वैश्विक अग्रणी बनाना है।

(ii) स्तंभ 4 कार्यबल कौशल, तकनीकी क्षमताओं और प्रशिक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, साथ ही निवेश बाधाओं को दूर करने और जहाज निर्माण क्षेत्र में निजी और अंतर्राष्ट्रीय निवेश को आकर्षित करने के लिए कानूनी, कराधान और नीति सुधारों को लागू करता है।

3. भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ जैविक उत्पादों के लिए पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA) पर हस्ताक्षर किए।



24 सितंबर 2025 को, भारत ने नई दिल्ली स्थित वाणिज्य भवन में ऑस्ट्रेलिया के साथ जैविक उत्पादों के लिए एक पारस्परिक मान्यता समझौते (MRA) पर हस्ताक्षर किए। भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार व्यवस्था (ECTA) के तहत यह समझौता दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मज़बूत करता है और नियामक बाधाओं को कम करके जैविक उत्पादों के व्यापार को सरल बनाने का लक्ष्य रखता है।

- MRA पर वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल, APEDA के अध्यक्ष अभिषेक देव, ऑस्ट्रेलियाई सरकार के प्रथम सहायक सचिव DAFF श्री टॉम ब्लैक, वाणिज्य विभाग की संयुक्त सचिव सुश्री पेटल ढिल्लों, FSSAI मानक सलाहकार डॉ. अलका राव और भारत में ऑस्ट्रेलिया के उप उच्चायुक्त श्री निक मैककैफ्रे सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

- MRA का कार्यान्वयन कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (MoC&I), भारत सरकार और कृषि, मत्स्य पालन एवं वानिकी विभाग (DAFF), ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा किया जाएगा। ये एजेंसियां समझौते का अनुपालन और सुचारू संचालन सुनिश्चित करेंगी।

Key Points:-

(i) भारत सरकार भारत को "विश्व का जैविक खाद्य भंडार" बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (NPOP) ने भारत की जैविक प्रणाली के लिए पारदर्शी और विश्वसनीय मानक स्थापित करने, MRA के अंतर्गत विश्वास और अनुपालन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

(ii) वित्त वर्ष 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया को भारत का जैविक निर्यात 8.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जिसकी कुल निर्यात मात्रा 2,781.58 मीट्रिक टन थी, जिसमें साइलियम भूसी, नारियल का दूध और चावल का प्रमुख योगदान रहा। MRA से भारतीय निर्यातकों की ऑस्ट्रेलिया के उच्च-मूल्य वाले जैविक बाज़ार तक पहुँच और बढ़ने की उम्मीद है।

(iii) MRA भारत और ऑस्ट्रेलिया के अधिकार क्षेत्र में उगाए और संसाधित जैविक उत्पादों को कवर करता है, जिसमें अप्रसंस्कृत पादप उत्पाद (समुद्री शैवाल, जलीय पौधे और ग्रीनहाउस फसलों को छोड़कर), एक या एक से अधिक पादप-मूल अवयवों से बने प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ और वाइन शामिल हैं। यह दोनों देशों में जैविक मानकों की मान्यता सुनिश्चित करता है।

4. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने भारत के पहले सेंट्रल टिशू बैंक और दिल्ली डेंटल काउंसिल के लिए कैशलेस 'वी-ऑफिस' का उद्घाटन किया।



सितंबर 2025 में, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने भारत के पहले सेंट्रल टिशू बैंक का उद्घाटन किया और मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज (MAIDS), नई दिल्ली में दिल्ली डेंटल काउंसिल (DDC) के लिए एक कैशलेस 'वी-ऑफिस' का शुभारंभ किया। इन पहलों का उद्देश्य दंत चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा वितरण, सामर्थ्य और पारदर्शिता में सुधार लाना है।

- MAIDS के पीरियोडोंटोलॉजी विभाग में अपनी तरह का पहला केंद्रीय ऊतक बैंक स्थापित किया गया है। यह मरीजों को दंत शल्य चिकित्सा के लिए आवश्यक उच्च-गुणवत्ता वाले ऊतक और अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, जिससे उन्नत उपचार समाधानों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित होगी।

- सेंट्रल टिशू बैंक के माध्यम से ऊतक प्रत्यारोपण की उपलब्धता से मरीजों को खुले बाजार से महंगे प्रत्यारोपण खरीदने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस पहल से दंत शल्य चिकित्सा की लागत में कम से कम 25% की कमी आने का अनुमान है, जिससे उपचार अधिक किफायती हो जाएगा।

Key Points:-

(i) ऊतक बैंक विशेष चिकित्सा उपकरणों से सुसज्जित है, जैसे कि अस्थि आरा मशीन, पराबैंगनी (UV) से सुसज्जित लेमिनार वायु प्रवाह कक्ष, और उन्नत स्टरलाइज़ेशन प्रणालियाँ। ये उपकरण दंत

चिकित्सा के लिए सुरक्षित, रोगाणुरहित और रोगमुक्त एलोग्राफ्ट का उत्पादन सुनिश्चित करते हैं।

(ii) दिल्ली डेंटल काउंसिल ने दंत चिकित्सक पंजीकरण और लाइसेंस नवीनीकरण को सरल बनाने के लिए पूरी तरह से कैशलेस और डिजिटल 'वी-ऑफिस' प्रणाली शुरू की है।

(iii) इसके साथ ही DDC भारत में पहली राज्य दंत परिषद बन गई है जिसने पूर्ण डिजिटल गवर्नेंस मॉडल अपनाया है, जिससे दंत चिकित्सा पेशेवरों के लिए पारदर्शिता और पहुंच में वृद्धि हुई है।

Key Points:-

(i) शिखर सम्मेलन का आयोजन "लोगों और ग्रह के लिए संतुलन बहाल करना: कल्याण का विज्ञान और अभ्यास" विषय पर आधारित होगा, जिसमें वैश्विक स्वास्थ्य और स्थिरता में पारंपरिक चिकित्सा की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

(ii) इस समझौते को द्वितीय शिखर सम्मेलन योजना समूह की बैठक के दौरान केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रतापराव जाधव और आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा की उपस्थिति में औपचारिक रूप दिया गया।

5. आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन दिसंबर 2025 में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे वैश्विक शिखर सम्मेलन की सह-मेजबानी करेंगे।



सितंबर 2025 में, आयुष मंत्रालय (आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन की संयुक्त मेजबानी के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

● पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरा WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 से 19 दिसंबर, 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वैश्विक विशेषज्ञ, नीति निर्माता और हितधारक एक साथ आएंगे।

6. तेलंगाना ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए RAMP योजना का महिला-केंद्रित संस्करण शुरू किया।



सितंबर 2025 में, तेलंगाना सरकार के WE हब ने महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए विश्व बैंक और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoMSME) द्वारा समर्थित, MSME प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने (RAMP) योजना का महिला-केंद्रित संस्करण लॉन्च किया।

● यह पहल तेलंगाना के 13 जिलों के 300 आवेदकों में से चुने गए 45 महिला-नेतृत्व वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को समर्पित बूट-कैंप और

त्वरण कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता प्रदान करेगी।

● यह कार्यक्रम दो वर्षों तक, मार्च 2027 तक चलेगा, जिसमें चयनित उद्यमों को निरंतर सहायता, मार्गदर्शन और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की जाएगी।

Key Points:-

(i) यह योजना क्षेत्र-विशिष्ट मार्गदर्शन, उत्पाद स्थिति निर्धारण, ई-कॉमर्स सहायता, बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) और बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) कनेक्शन, और नवाचार-संचालित बाजार विकास के अवसर प्रदान करेगी।

(ii) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (nimsme) एक प्रमुख कार्यान्वयन भागीदार है, जो जमीनी स्तर पर प्रभाव सुनिश्चित करने और महिला उद्यमिता को मजबूत करने के लिए WE हब के साथ मिलकर काम कर रहा है।

(iii) RAMP योजना विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे 30 जून, 2022 को लॉन्च किया गया है, जिसका परिव्यय वित्त वर्ष 2022-वित्त वर्ष 2027 के लिए 6,062.45 करोड़ रुपये (808 मिलियन अमरीकी डॉलर) है, जिसका लक्ष्य देश भर में 5.55 लाख MSMEs को लाभान्वित करना है।

INTERNATIONAL

1. 69वां IAEA महासम्मेलन वियना, ऑस्ट्रिया में आयोजित हुआ और मालदीव नए सदस्य राज्य के रूप में शामिल हुआ।



अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) का 69वां महाधिवेशन (GC) 15 से 19 सितंबर, 2025 तक ऑस्ट्रिया के वियना अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में परमाणु सुरक्षा, संरक्षा और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया और साथ ही IAEA के बजट और कार्यक्रमों को भी मंजूरी दी गई।

● 69वें जी.सी. का विषय था "सतत विकास के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना", जिसमें शांति, सुरक्षा और वैश्विक विकास के चालक के रूप में परमाणु विज्ञान पर जोर दिया गया।

● सम्मेलन में 3,000 से ज़्यादा पंजीकृत प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें 180 IAEA सदस्य देशों में से 153 देशों के 2,757 प्रतिनिधि शामिल थे। भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व परमाणु ऊर्जा आयोग (AEC) के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) के सचिव डॉ. अजीत कुमार मोहंती ने किया।

Key Points:-

(i) 15 सितंबर, 2025 को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) में स्लोवाकिया के राजदूत, पीटर ब्यूरियन, 69वीं GC के अध्यक्ष चुने गए। उपाध्यक्षों में ईरान, अर्जेंटीना, फ्रांस, आइवरी कोस्ट, मंगोलिया, न्यूज़ीलैंड, पोलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल थे, जिससे विविध प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ।

(ii) 69वीं जी.सी. बैठक के दौरान मालदीव को IAEA का नवीनतम सदस्य घोषित किया गया, जिससे संगठन की सदस्यता बढ़कर 181 हो गई।

(iii) इसके अतिरिक्त, 16-17 सितंबर, 2025 को “जल के लिए परमाणु” विषय पर IAEA विज्ञान फोरम का आयोजन किया गया, जिसमें दिखाया गया कि किस प्रकार परमाणु और समस्थानिक प्रौद्योगिकियां वैश्विक जल चुनौतियों का समाधान कर सकती हैं।

BANKING & FINANCE

1. डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण तंत्र को मज़बूत करने हेतु RBI ने नए निर्देश जारी किए।



सितंबर 2025 में, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 के अंतर्गत 'भारतीय रिज़र्व बैंक (डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए प्रमाणीकरण तंत्र) निर्देश, 2025' जारी किए। नए दिशानिर्देशों का उद्देश्य भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में सुरक्षा को बढ़ाना है और ये 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे।

• ये निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली (PSS) अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 और 10(2) के तहत जारी किए गए हैं, जिससे ये बैंकों और गैर-बैंकों सहित सभी भुगतान प्रणाली प्रदाताओं और प्रतिभागियों पर लागू होते हैं।

• डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए, कार्ड-प्रेजेंट लेनदेन को छोड़कर, कम से कम एक प्रमाणीकरण कारक गतिशील रूप से निर्मित या सिद्ध होना चाहिए, जिससे लेनदेन सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत सुनिश्चित हो सके।

Key Points:-

(i) भुगतान साधनों के जारीकर्ता को ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए प्रमाणीकरण तंत्र की मजबूती, विश्वसनीयता और अखंडता सुनिश्चित करनी होगी।

(ii) हालाँकि यह सभी सीमा-पार लेनदेन पर लागू नहीं होता है, RBI ने अनिवार्य किया है कि कार्ड जारीकर्ता 1 अक्टूबर, 2026 तक कार्ड-नॉट-प्रेजेंट (CNP) सीमा-पार लेनदेन से निपटने के लिए जोखिम-आधारित तंत्र लागू करें।

ECONOMY & BUSINESS

1. SDHI ने भारत में स्वदेशी अपतटीय पोत निर्माण को बढ़ावा देने के लिए रॉयल IHC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



सितंबर 2025 में, भारत की सबसे बड़ी जहाज निर्माण और भारी निर्माण कंपनी, स्वान डिफेंस एंड हैवी इंडस्ट्रीज (SDHI), जिसे पहले रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (RNEL) के नाम से जाना जाता था, ने नीदरलैंड स्थित अपतटीय तेल और गैस पोत

विशेषज्ञ, रॉयल IHC के साथ भारत में उन्नत पोतों के संयुक्त रूप से डिजाइन, निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- MoU में रॉयल IHC के भारतीय प्रतिनिधि, अलार इंफ्रास्ट्रक्चर, के साथ गुजरात के पिपावा बंदरगाह स्थित SDHI के आधुनिक शिपयार्ड में अपतटीय पोतों के डिजाइन, निर्माण और रेट्रोफिटिंग पर सहयोग करना शामिल है।

- इस साझेदारी का उद्देश्य पिपावा बंदरगाह स्थित SDHI के शिपयार्ड क्षमताओं का लाभ उठाते हुए अपतटीय निर्माण पोत, पाइप बिछाने वाले पोत और बहुउद्देश्यीय अपतटीय सहायक पोतों का निर्माण करना है।

Key Points:-

(i) यह सहयोग भारत की स्वदेशी जहाज निर्माण क्षमता को बढ़ाने, तकनीकी विशेषज्ञता को मज़बूत करने और उन्नत विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

(ii) यह गठबंधन सरकार की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों का समर्थन करता है, जिससे रक्षा और समुद्री बुनियादी ढाँचे में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलता है।

MOUs and Agreement

1. एशियाई पाम ऑयल एलायंस, CPOPC और सॉलिडारिडाड ने भारत में सतत पाम ऑयल को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।



सितंबर 2025 में, एशियाई पाम ऑयल एलायंस (APOA), पाम ऑयल उत्पादक देशों की परिषद (CPOPC) और सॉलिडारिडाड नेटवर्क एशिया लिमिटेड (SNAL) ने भारत और दक्षिण एशिया में पाम ऑयल मूल्य श्रृंखला में उत्पादक-उपभोक्ता सहयोग को मजबूत करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए मुंबई, महाराष्ट्र में तीन साल के त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

- एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन की देखरेख करेगा। APOA और CPOPC द्वारा JWG की सह-अध्यक्षता की जाएगी, जबकि सॉलिडारिडाड तकनीकी सचिवालय के रूप में कार्य करेगा, जो तीन वर्षों की अवधि में सतत प्रथाओं के समन्वय और निगरानी को सुनिश्चित करेगा।

- समझौता ज्ञापन का उद्देश्य इंडोनेशिया सस्टेनेबल पाम ऑयल (ISPO), मलेशियाई सस्टेनेबल पाम ऑयल (MSPO) और भारतीय पाम ऑयल सस्टेनेबिलिटी (IPOS) ढाँचे सहित विभिन्न देशों में पाम ऑयल सस्टेनेबिलिटी मानकों को संरक्षित और सुसंगत बनाना है, जिससे सुसंगत और विश्वसनीय सस्टेनेबिलिटी प्रमाणन की सुविधा मिल सके।

- यह पहल ट्रेस करने योग्य, छोटे किसानों को शामिल करने वाली और NDPE (वनों की कटाई नहीं, पीट नहीं, शोषण नहीं) के अनुरूप सोर्सिंग पर

धोखाधड़ी वाले मोबाइल कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए गए हैं और 48 लाख संदिग्ध लेन-देन रोके गए हैं, जिससे लगभग 140 करोड़ रुपये की बचत हुई है।

SPORTS

1. FIFA ने 2026 विश्व कप के लिए तीन आधिकारिक शुभंकर घोषित किए।



सितंबर 2025 में, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन (FIFA) ने हाल ही में 23वें फीफा विश्व कप, 2026 के लिए तीन आधिकारिक mascots-क्लच, ज़ायू और मेपल - घोषित किए। यह टूर्नामेंट 26 जून से 19 जुलाई, 2026 तक संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जो पहली बार तीन देशों में आयोजित किया जाएगा।

- क्लच, एक गंजा चील, एक मिडफील्डर के रूप में खेलता है। यह चरित्र साहसी, आशावादी, एकजुट और निडर है, जो मैदान पर टीम के साथियों को प्रेरित करने और उनका उत्साह बढ़ाने के लिए जाना जाता है।

- ज़ायू, एक जगुआर, स्ट्राइकर के रूप में कार्य करता है। चुस्त और रचनात्मक, ज़ायू मैक्सिकन संस्कृति, ताकत और गौरव का प्रतीक है, साथ ही देश की विरासत और फुटबॉल भावना को भी उजागर करता है।

- मेपल, एक मूस, गोलकीपर की भूमिका निभाता है। संगीत और कला के प्रति जुनूनी, दृढ़ निश्चयी और एक मिलनसार यात्री, मेपल को शानदार बचाव और टीम वर्क को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र ने 25 सितंबर 2025 को विश्व समुद्री दिवस मनाया।



संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 25 सितंबर 2025 को विश्व समुद्री दिवस (WMD) मनाया, जिसमें समुद्री गतिविधियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया और वैश्विक विकास में समुद्री उद्योग के योगदान को मान्यता दी गई। इस वार्षिक दिवस का उद्देश्य जीवन, आजीविका और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में महासागरों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है।

- 2025 में WMD दिवस 25 सितंबर को मनाया जाएगा, जबकि 2024 में WMD दिवस 26 सितंबर को मनाया जाएगा, और 2026 में WMD दिवस 25 सितंबर को मनाया जाएगा। यह दिवस हर साल सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है।

- 2025 का विषय "हमारा महासागर, हमारा दायित्व, हमारा अवसर" है, जो जीवन को सहारा देने, आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और वैश्विक आजीविका को बनाए रखने में महासागर की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है।

Key Points:-

(i) विश्व समुद्री दिवस पहली बार 17 मार्च 1978 को मनाया गया था, जो 1958 के अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) कन्वेंशन के लागू होने का प्रतीक था। तब से, यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी IMO के नेतृत्व में विश्व स्तर पर मनाया जाता रहा है।

(ii) थीम को बढ़ावा देने के लिए, IMO मुख्यालय और अन्य वैश्विक स्थलों को नीले रंग से प्रकाशित किया गया। मुख्यालय में समुद्री संरक्षण और सतत समुद्री प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए "ओशन विद डेविड एटनबरो" फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया।

(iii) आधिकारिक समानांतर कार्यक्रम 29 सितंबर से 1 अक्टूबर, 2025 तक दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में हुआ। इसमें उच्च स्तरीय पैनल चर्चाएं शामिल थीं, जिसमें 2025 थीम के साथ संरेखित टिकाऊ समुद्री प्रथाओं पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों और हितधारकों को एक साथ लाया गया।

2. संयुक्त राष्ट्र ने 26 सितंबर 2025 को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।



संयुक्त राष्ट्र (UN) ने 26 सितंबर 2025 को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का

पालन किया। इस दिवस का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों के खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना और एक परमाणु मुक्त विश्व के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को प्रोत्साहित करना है।

- 26 सितंबर 2013 को, संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रस्ताव A/RES/68/32 को अपनाया, जिसके तहत हर वर्ष 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में नामित किया गया। यह प्रस्ताव 2013 में UNGA की पहली उच्च स्तरीय परमाणु निरस्त्रीकरण बैठक के बाद वैश्विक प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

- इस अंतरराष्ट्रीय दिवस का पहला पालन 26 सितंबर 2014 को किया गया, जिसने परमाणु निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक वैश्विक अवलोकनों की शुरुआत की।

- NWFZs क्षेत्रीय संधियाँ हैं, जिन्हें UNGA (Res. 3472) द्वारा मान्यता दी गई है, जो गैर-प्रसार को मजबूत करने, शांति को बढ़ावा देने और अंतरराष्ट्रीय सत्यापन के माध्यम से किसी भी परमाणु हथियार की अनुपस्थिति सुनिश्चित करती हैं। पहला NWFZ लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में स्थापित हुआ (Tlatelolco संधि, 1967), इसके बाद दक्षिण प्रशांत (Rarotonga, 1985), दक्षिण-पूर्व एशिया (Bangkok, 1995), अफ्रीका (Pelindaba, 2006), और मध्य एशिया (कज़ाखस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, 2006) में स्थापित हुआ।

Key Points:-

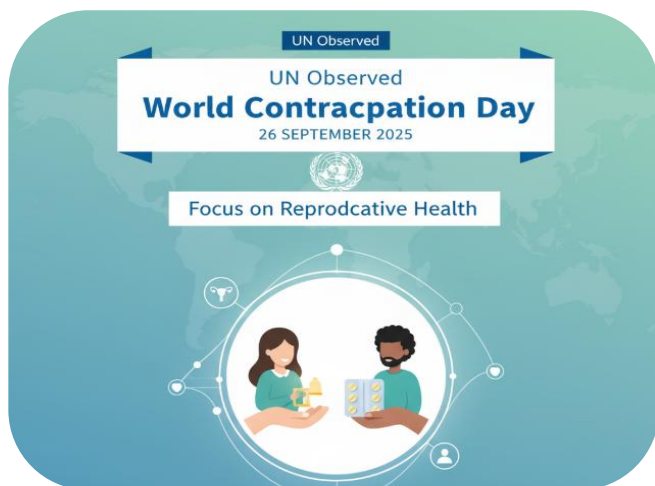
(i) 2017 में अपनाई गई और 22 जनवरी 2021 से प्रभावी, TPNW दो दशकों में पहली बहुपक्षीय विधिक रूप से बाध्यकारी संधि है, जो सभी परमाणु हथियार गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाती है। यह संधि एक परमाणु-मुक्त विश्व के प्रति अंतरराष्ट्रीय

प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

(ii) मुख्य संधियों में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मूल रणनीतिक शस्त्र कमी संधि (START, 1994–2009) शामिल है। न्यू START संधि 4 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी गई है, हालांकि रूस ने 21 फरवरी 2023 को इसमें से अपना भाग लेने को निलंबित कर दिया और 2 नवंबर 2023 को समग्र परमाणु परीक्षण निषेध संधि (CTBT) से बाहर हो गया।

(iii) 2025 तक, दुनिया में लगभग 12,241 परमाणु हथियार मौजूद हैं। वैश्विक जनसंख्या का 50% से अधिक हिस्सा ऐसे देशों में रहता है जिनके पास परमाणु हथियार हैं या जो परमाणु गठबंधनों में शामिल हैं। TPNW की 3री बैठक 3–7 मार्च 2025 को UN मुख्यालय में आयोजित की गई थी, जिसमें एक घोषणा अपनाई गई जिसने परमाणु निरस्त्रीकरण के प्रति वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत किया।

3. विश्व गर्भनिरोधक दिवस 2025, प्रजनन स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए 26 सितंबर को मनाया।



विश्व गर्भनिरोधक दिवस हर साल 26 सितंबर को दुनिया भर में गर्भनिरोधक विकल्पों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य के लिए सूचित विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए मनाया

जाता है। 2025 में, यह दिवस 19वीं बार मनाया जाएगा।

● विश्व गर्भनिरोधक दिवस 2025 का विषय था "सभी के लिए एक विकल्प। योजना बनाने की स्वतंत्रता, चुनने की शक्ति," जो गर्भनिरोधक, प्रजनन स्वायत्तता और परिवार नियोजन तक सार्वभौमिक पहुँच पर प्रकाश डालता है।

● परिवार नियोजन में गर्भनिरोधकों के महत्व पर जोर देने के लिए 2007 में 10 अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन संगठनों द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। तब से, यह दिवस प्रतिवर्ष 26 सितंबर को मनाया जाता है।

Key Points:-

(i) गर्भनिरोधक, जिसे जन्म नियंत्रण भी कहा जाता है, दवाओं, उपकरणों या सर्जरी के माध्यम से गर्भधारण को रोकने के तरीकों को संदर्भित करता है। यह यौन स्वास्थ्य, प्रजनन योजना और महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

(ii) गर्भनिरोधक विधियों में प्रतिवर्ती और स्थायी विकल्प शामिल हैं जैसे अवरोध विधियाँ (कंडोम, स्पंज, डायोफ्राम), नसबंदी, हार्मोनल विधियाँ (गोलियाँ, पैच, योनि रिंग), अंतर्गर्भाशयी उपकरण (IUDs) और आपातकालीन विधियाँ।

(iii) वैश्विक स्तर पर, गर्भधारण से बचने की इच्छा रखने वाली 25 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं सुरक्षित या आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। UNFPA के एक सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 17.2 करोड़ लोग अभी भी किसी भी प्रकार के गर्भनिरोधक का इस्तेमाल नहीं करते हैं।

DEFENCE

1. रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ 97 तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट्स की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपये का समझौता किया



सितंबर 2025 में, रक्षा मंत्रालय (MoD) ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ 97 तेजस मार्क-1ए फाइटर जेट्स की खरीद के लिए 62,370 करोड़ रुपये का समझौता किया। यह अधिग्रहण डिफेंस अकिज़िशन प्रोसीजर 2020 के बाय इंडिया-स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित (IDDM) श्रेणी के तहत भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है।

- इस समझौते में 68 सिंगल-सीट फाइटर और 29 ट्विन-सीट ट्रेनर शामिल हैं, साथ ही आवश्यक उपकरण भी शामिल हैं। यह स्वदेशी LCA मार्क-1ए फाइटर का दूसरा आदेश है, फरवरी 2021 में 83 एयरक्राफ्ट के आदेश के बाद, जिसकी कीमत लगभग 48,000 करोड़ रुपये थी। अब IAF ने कुल 180 से अधिक तेजस एयरक्राफ्ट के आदेश दे दिए हैं।

- तेजस मार्क-1A परियोजना का समर्थन लगभग 105 भारतीय कंपनियों के नेटवर्क द्वारा किया जा रहा है, जो सीधे घटकों के निर्माण में शामिल हैं, जिससे स्वदेशी उद्योग और स्वदेशीकरण को बढ़ावा मिलता है।

- रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 97 तेजस मार्क-1A जेट्स की डिलीवरी 2027-28 से शुरू होगी और छह वर्षों में पूरी की जाएगी, जो IAF के आधुनिकीकरण योजनाओं के अनुरूप है।

Key Points:-

(i) तेजस मार्क-1A एक स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (LCA) है, जिसमें 64% से अधिक स्वदेशी सामग्री है और इसमें पिछले LCA Mk1A अनुबंध की तुलना में 67 अतिरिक्त घटक शामिल हैं।

(ii) इसमें उन्नत एवियोनिक्स, राडार सिस्टम और आधुनिक हथियार लगे हैं, जैसे कि UTTAM AESA राडार, स्वयं रक्षा कवच (Swayam Raksha Kavach) और उन्नत कंट्रोल एक्ट्यूएटर, जो इसे लंबी दूरी से कई हथियार लॉन्च करने में सक्षम बनाते हैं।

(iii) पहले तेजस जेट्स IAF में जुलाई 2016 में शामिल किए गए थे। यह एक सिंगल-इंजन, लाइटवेट मल्टी-रोल फाइटर है, जिसे मूल रूप से MiG-21 को बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया था। वर्तमान मार्क-1A संस्करण भारत की स्वदेशी रक्षा और वायु श्रेष्ठता क्षमताओं को और मजबूत करता है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. NASA और NOAA ने अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए तीन अंतरिक्ष विज्ञान मिशन लॉन्च किए।



24 सितंबर, 2025 को, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन (NASA) ने राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन (NOAA) के सहयोग से, अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी तथा अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियों

पर इसके प्रभावों का अध्ययन करने के लिए हाल ही में तीन मिशन - इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब (IMAP), स्पेस वेदर फॉलो-ऑन-लैग्रेंज 1 (SWFO-L1), और कैरुथर्स जियोकोरोना वेधशाला (CGO) - लॉन्च किए।

- मिशन को फ्लोरिडा, अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किया गया।

- IMAP, जिसका मूल्य लगभग 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, एक हीलियोफिजिक्स मिशन है, जिसे हीलियोस्फीयर की सीमा - सौर वायु द्वारा निर्मित सौर मंडल के चारों ओर सुरक्षात्मक चुंबकीय बुलबुला - और अंतरतारकीय माध्यम के साथ इसकी अंतःक्रिया का अध्ययन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- NOAA द्वारा संचालित, SWFO-L1 पृथ्वी की तकनीकी प्रणालियों और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए वास्तविक समय में अंतरिक्ष मौसम की निगरानी करता है। पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर, सूर्य-पृथ्वी L1 बिंदु पर स्थित, यह सौर वायु और कोरोनाल मास इजेक्शन (CME) को पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ही देख लेता है, जिससे अंतरिक्ष मौसम के पूर्वानुमान के लिए महत्वपूर्ण समय मिल जाता है।

Key Points:-

(i) CGO पहला मिशन है जो पृथ्वी के बाह्यमंडल, यानी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत, का अध्ययन करने के लिए समर्पित है, जिसमें तटस्थ हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा उत्सर्जित पराबैंगनी (यूवी) प्रकाश का अवलोकन किया जाएगा। इस मिशन का नाम डॉ. जॉर्ज आर. कैरुथर्स के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1972 में अपोलो 16 चंद्रमा मिशन के लिए पहला यूवी टेलीस्कोप विकसित किया था।

(ii) ये तीनों मिशन अंतरिक्ष विज्ञान को आगे बढ़ाने में NASA-NOAA सहयोग को दर्शाते हैं। सभी मिशन

कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए प्रक्षेपित किए गए, जो आधुनिक अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी-सार्वजनिक साझेदारी की भूमिका को दर्शाता है।

(iii) इन मिशनों से हेलियोफिजिक्स, अंतरिक्ष मौसम और पृथ्वी के बाहरी वायुमंडल की समझ बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उपग्रहों, संचार प्रणालियों और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा में मदद मिलेगी, साथ ही पृथ्वी और अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियों को प्रभावित करने वाली सौर घटनाओं के लिए पूर्वानुमान क्षमताओं में सुधार होगा।

Static GK

Australia	राष्ट्रपति : एंथनी अल्बानीज़	राजधानी : कैनबरा
Indian Air Force (IAF)	वायुसेना प्रमुख (CAS) : एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत (ए.पी.) सिंह	मुख्यालय: नई दिल्ली
Ministry of AYUSH	मंत्री: प्रतापराव गणपतराव जाधव	सचिव: राजेश कोटेचा
Telangana	मुख्यमंत्री: रेवंत रेड्डी	राज्यपाल: जिष्णु देव वर्मा
International Atomic Energy Agency (IAEA)	महानिदेशक (DG) : राफेल मारियानो ग्रॉसी	मुख्यालय : वियना, ऑस्ट्रिया
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
National Aeronautics and Space Administration (NASA)	प्रशासक : सीन डफी	मुख्यालय : वाशिंगटन डी.सी., संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
International Maritime Organization (IMO)	महासचिव : आर्सेनियो डोमिंगुएज़	मुख्यालय: लंदन, यूनाइटेड किंगडम (UK)

United Nations (UN)	महासचिव : एंटोनियो गुटेरेस	मुख्यालय: न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका (USA)
---------------------	----------------------------	--